

सांकेतिक समाचार

संजीव हत्याकांड के आरोपी लव कुमार ने न्यायलय में किया आत्मसमर्पण

साहिबगंजः साहिबगंज के चर्चित व्यवसायी संजीव कुमार गुप्ता उर्फ गुड़ी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। इस हत्याकांड में आरोपी लव कुमार ने गुरुवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, साहिबगंज की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। न्यायलय ने उसे न्यायिक हिरासत में लेते हुए साहिबगंज जेल भेज दिया है। जात हो कि 4 मई 2025 की शाम 7:30 बजे, कॉलेज रोड रिथ चैटी दुग्ध मंदिर के समीप रिथ इलेक्ट्रोनिक डुकान में घुसकर अज्ञात अपराधियों ने संजीव गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी और व्यवसायियों में भय का माहौल बढ़ाया गया था। घटना के तुरंत बाद मूरक की मां भूंजू देवी ने नगर थाना में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर्त्तव्य थी, जिसे कांड संख्या 74/2025 के तहत संज्ञान में लिया गया। जांच के क्रम में पुलिस ने कुश कुमार को हिरासत में लिया, जिसके बायां के अधार पर लव कुमार का नाम इस हत्याकांड में समाने आया पुलिस ने मामले के अधार तात्पर्यमाई डंड मंडल को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस सुन्नों के अनुसार, एक डंड मंडल ने इस पूरी घटना की योजना बनाई थी और लव कुमार सहित अन्य अपराधियों को अंजाम तक पहुंचने का निर्देश दिया था।

देवघर के छात्र नेता रवि वर्मा ने छात्रों की समस्या का किया समाधान



देवघर से दिव्य दिनकर संवाददाता प्रेम रंजन झा

कांग्रेस छात्र संगठन देवघर एनएसयूआई के छात्र नेता रवि वर्मा ने देवघर के ए.एस. कॉलेज में छात्र/छात्राओं को एडमिट कार्ड लेने के दौरान समस्या तथा अन्य पद्धति के दौरान हो रही विभिन्न समस्याएँ देखते हुए उनका मौके पर ही समाधान किया तथा वहां उपस्थित सभी छात्र/छात्राओं को छात्र नेता रवि वर्मा ने आश्वाशन दिया कि उनको पद्धति के दौरान किसी भी तरह की समस्या यदि हो रही हो तो वो अवगत कराएं भारतीय छात्र संगठन एनएसयूआई उनकी हर समस्या का कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक समाधान करेंगी मौके पर छात्र नेता आदर्श केशरी, सैफ दनिश, पीयूष केशरी, मनोज कुमार, सुनील यादव, पिंटू यादव आदि दर्जनों सदस्य मौजूद थे।

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

चद्वारा संवाददाता विजय यादव

चंद्वारा थाना क्षेत्र के कांड संख्या 22/2023 के तहत दर्ज दुष्कर्म मामले में आरोपी जूनैर अंसारी (20 वर्ष) को दोपी करार देते हुए कोडरमा की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वितीय की अदालत में 10 वर्षों के कटोर कारणावास की सजा सुनाई है। वह फैसला 15 मई 2025 को सुनाया गया।

अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोपी पाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जूबैर अंसारी ने पिंडिया को देखते हुए कोडरमा की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वितीय की अदालत में 10 वर्षों के कटोर कारणावास की सजा सुनाई है। वह फैसला 15 मई 2025 को सुनाया गया।

अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोपी पाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जूबैर अंसारी ने पिंडिया को देखते हुए कोडरमा की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वितीय की अदालत में 10 वर्षों के कटोर कारणावास की सजा सुनाई है। वह फैसला 15 मई 2025 को सुनाया गया।

नगर में चल रहे अवैध चुलाई शराब व्यापार

हुआ भंडाफोड़ 10 लीटर शराब जप्त

रिपोर्ट अविनाश मंडल

पाकुड़: पाकुड़ गुरुवार को उत्पाद विभाग की टीम ने नगर परिषद क्षेत्र स्थित कितांगीर मरागमय बेसरा के घर पर छायाचारी की छायाचारी के क्रम में 10 लीटर अवैध चुलाई शराब एवं 230 किलो जल मिश्रित जावा महुआ बरामद किया गया। जल मिश्रित जावा महुआ को घटनास्थल पर विनिष्ठ किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध फरार अधिकारी दर्ज किया गया।

सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गल्स के सीबीएसई दसवीं बोर्ड परिणाम पर छह अत्वल छात्राएं हुए सम्मानित

रिपोर्ट - अविनाश मंडल

पाकुड़: पाकुड़ समाहरायालय स्थित सभागृह में उपायुक्त मनोज कुमार व पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी साईमन मराडी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी प्रीतिलता सुर्मुर्ज जिला शिक्षा पदाधिकारी अंगीपारी, जिला शिक्षा अधीक्षक नवन कुमार, पाकुड़ एवं महेशपुर एसडीपीओ ने 60 प्रारिषद से अधिक अंक लाने वाले 6 छात्राएं को प्रशस्ति प्रदान करायी देखा। उन्होंने शिक्षाकों के समर्पण और छात्राएं की मेहनत की सराहना की। उपायुक्त ने सभी छात्राएं को परापरण किया गया है। उन्होंने शिक्षाकों के समर्पण और छात्राएं की मेहनत की सराहना की। उपायुक्त ने सभी छात्राएं के उत्तरांग विविध की कामना करते हुए अग्रे भी ऐसे ही गोरवपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने की शुभकामनाएं दी।



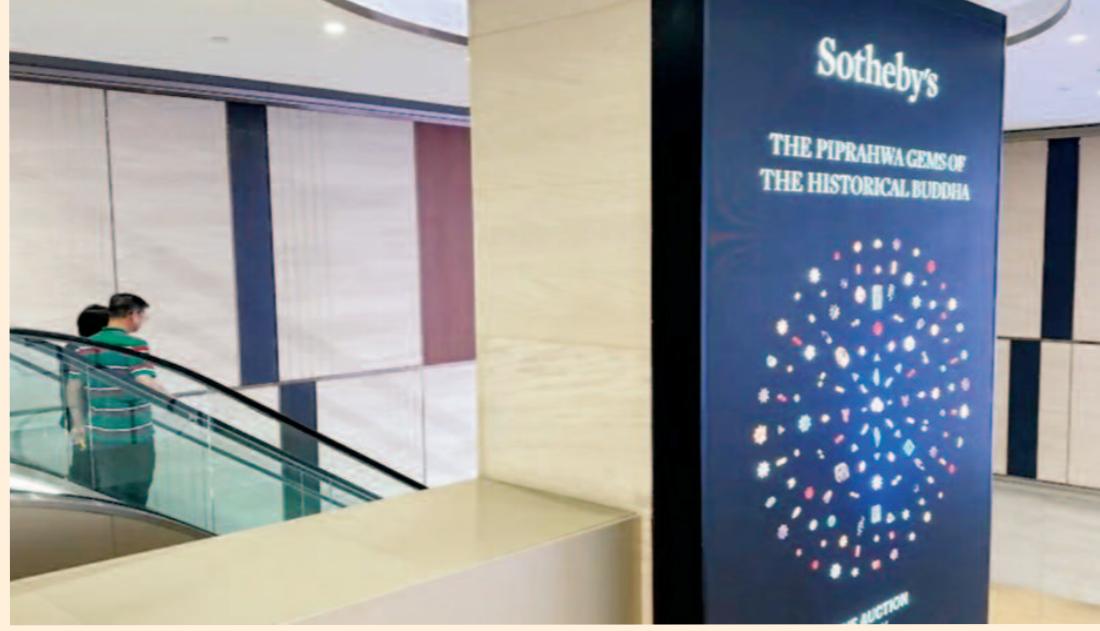
रिपोर्ट - अविनाश मंडल

भारत की अनमोल धरोहर की नीलामी

>> **विचार**

“ नीलामी करने वाली
कंपनी सोदबीज़
ब्रितानी मूल की
बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो
सांस्कृतिक महत्व की धरोहरों
की नीलामी करने के कारण
अक्सर विवादों में रहती है। छह
साल पहले न्यूज़ीलैंड के माओरे
आदिवासियों की काष्ठ
कलाकृति की लगभग छह
करोड़ रुपये में हुई नीलामी को
लेकर विवाद हुआ था और
सरकार से कलाकृति वापस
लाने की मांगों की गई थी।
भगवान बुद्ध के शब्दों द्वारा की
नीलामी तो और भी विवादास्पद
है। दबों की नीलामी विलयम
पेपे के परपोते क्रिस पेपे करान
चाहते हैं जो फिल्म निर्माता हैं
और हॉलीवुड में काम करते हैं।
उनका कहना है कि ये रत
भगवान बुद्ध की अस्थियों या
अवशेषों का हिस्सा नहीं हैं।

शिवकान्त शर्मा
हांगकांग में होने वाली भगवान बुद्ध के अनमोल श्रद्धा रत्नों की नीलामी ने एक बार फिर इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या विश्व की अनमोल सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को नीलाम होने देना सही है? गत सप्ताह जिन 371 रत्नों और स्वरण एवं रजत पत्रकों की नीलामी होने वाली थी वे आज से लगभग सवा सौ साल पहले 1898 में उत्तरप्रदेश के सिद्धार्थ नगर जलि के पिपरहवा गांव में एक बौद्ध स्तूप की खुदाई में मिले थे। पिपरहवा नेपाल की सीमा पर स्थित है और माना जाता है कि शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु वहीं पर थी। खुदाई इस इलाके के ब्रितानी जर्मीनियर विलियम क्रैक्सटन पेपे ने कर्हाई थी जो पेशे से इंजीनियर थे। खुदाई में 130 फुट व्यास वाले ईंटों से बने स्तूप के भीतर पथर का एक संदूक मिला था जिसमें पांच पाषाण कलश थे। इनमें भगवान बुद्ध की अस्थियाँ और भ्रम्म के साथ 1800 से अधिक मोती, माणिक, पुखराज और नीलम जैसे रत्न और सोने व चांदी के पत्रक रखे थे जिन पर बौद्ध आकृतियाँ बनी हुई थीं। इनमें से एक कलश पर ब्राह्मी लिपि में प्राचीन पाली में लिखा था कि 'इस स्मारक स्तूप में भगवान बुद्ध की वे अस्थियाँ विराजमान हैं जो उनके शाक्यवंशी स्वजनों को मिली थीं। कुशीनगर में भगवान बुद्ध के परिनिवारण के बाद उनकी अस्थियाँ शाक्यवंशियों ने चारों दिशाओं से आए आठ गणराज्यों के प्रतिनिधियों में बांट दी थीं ताकि वे अपने-अपने यहां स्तूप बनाकर उनकी स्थापना कर सकें और अधिक से अधिक लोग उनका दर्शन करने जा सकें। इस प्रकार अस्थियाँ आठ गणराज्यों के स्तूपों में रखी गई थीं। माना जाता है कि पिपरहवा का स्तूप उन्हीं में से एक है जिसे एक ब्राह्मण ने महात्मा बुद्ध के शाक्यवंशियों के लिए बनवाया था। इसलिए इसे पुरातत्व की सबसे बड़ी खोजों में गिना गया। स्तूपों में बुद्ध की अस्थियों के साथ बहुमूल्य रत्न, सोने और चांदी के पत्रकों और मुद्राओं को रखने की परंपरा भी थी जिसके लिए लोग दिल खोलकर दान देते थे। विलियम पेपे ने अपने रिकॉर्ड में लिखा है कि खोज के पुरातात्त्विक और धार्मिक महत्व को समझते ही उन्होंने यह



धरोहर ब्रितानी सरकार के हवाले कर दी थी। सरकार ने रत्नों और अस्थियों को अलग करते हुए रत्नों का छठा हिस्सा पेपे को दे दिया। बाकी बचे रत्नों और अस्थियों में से कुछ हिस्सा बौद्ध देश थाइलैण्ड के राजा चू़डालंकरण द्वारा भेजे गए भिक्षुदूत को दिया और बाकी कोलकाता और कोलंबो के संग्रहालयों में भेज दिया था। हांगकांग में जिन रत्नों और सोने-चांदी के पत्रकों की नीलामी की कोशिश हो रही है वे वही हैं जो ब्रितानी सरकार ने विलियम पेपे को दिए थे। नीलामी करने वाली कंपनी सोदबीज़ ब्रितानी मूल की बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो सांस्कृतिक महत्व की धरोहरों की नीलामी करने के कारण अक्सर विवादों में रहती है। छह साल पहले न्यूज़ीलैंड के माओरी आदिवासियों की काष्ठ कलाकृति की लगभग छह करोड़ रुपये में हुई नीलामी को लेकर विवाद हुआ था और सरकार से कलाकृति वापस लाने की मांगें की गई थीं। भगवान बुद्ध के श्रद्धा रत्नों की नीलामी तो और भी विवादाप्त है। रत्नों की नीलामी विलियम पेपे के परपते क्रिस पेपे कराना चाहते हैं जो फिल्म निर्माता है और हॉलीवुड में काम करते हैं।

उनका कहना है कि ये रत्न भगवान बुद्ध की अस्थियों या अवशिष्टों का हिस्सा नहीं हैं। इन्हें लोगों ने श्रद्धा स्वरूप अस्थियों के साथ रखा था। इनका कोई धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व नहीं है। उन्होंने कई बौद्ध भिक्षुओं, मठों और विद्वानों से पूछने के बाद ही इन्हें नीलाम करने का फैसला किया है ताकि ये किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास चले जाएं जो इनकी सही देखभाल और सार्वजनिक प्रदर्शनी कर सके। उनका कहना है कि उनके परदादा को वहीं रत्न और पत्रक दिए गए थे जो संग्रह में एक से अधिक संख्या में मौजूद थे। इसलिए जिन्हें नीलाम किया जा रहा है उनके जैसे दूसरे रत्न और पत्रक कोलकाता, बैंकाक और कोलंबो के संग्रहालयों में मौजूद हैं। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने इन्हें दान करने के लिए कई बौद्ध मठों और बौद्ध देशों के संग्रहालयों से संपर्क किया था पर कहीं से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। लेकिन दुनियाभर के बहुत से बौद्ध मतावलंबी क्रिस पेपे के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हैं। न ही वे नीलामी करने वाली कंपनी सोदबीज़ के इस दावे से संतुष्ट हैं कि उन्होंने इस

नीलामी के सारे नैतिक और कानूनी पक्षों को नाप-तोल कर ही नीलामी करने का फैसला किया था। लंदन के प्राच्यविद्या एवं अफ्रीकी अध्ययन संस्थान (सोआस) में दिक्षिण एशियाई कला के विशेषज्ञ प्रो. एशली टॉम्पसन और संग्रहपाल कोनान चोंग का कहना है कि बुद्ध धर्मवर्लंबियों के अनुसार भगवान बुद्ध के अस्थिकलशों में अस्थियों और भस्म के साथ डाले गए श्रद्धा रत्नों को अलग कैसे माना जा सकता है? वे अस्थियों के स्पर्श मात्र से उनका अभिन्न भाग बन चुके हैं। उनका वही महत्व और स्थान होगा जो उनकी अस्थियों का है। ब्रेतानी महाबोधि समिति के विद्वान अमल अभ्यवर्धने का कहना है कि भगवान बुद्ध का उद्देश है कि दूसरों की संपत्ति उनकी अनुमति के बिना नहीं लेनी चाहिए। शाक्यवंशियों को यह धरोहर इसलिए सौंपी गई थी कि वे स्मारक बनाकर उन्हें श्रद्धालुओं के दर्शन और पूजा के लिए मुख्य बना सकें। उन्होंने स्तुप बनाकर वही किया। औपनिवेशिक शासकों का ऐपरहवा की खुदीई से मिली शाक्यवंशियों की सांस्कृतिक धरोहर पर मालिकाना हक कैसे हो

या? विवाद से चौतर हाकर भारत सरकार का कानूनी कार्रवाई की धमकी देनी पड़ी है जिसके बाद सोटीबोज़ ने नीलामी को स्थगित कर दिया है ताकि सभी पक्षों के बीच बातचीत से कोई समाधान निकाला जा सके। पिपरहवा की खुदाई से मिले रख इसा से कम से कम दो से ढाई सौ साल पुराने होने के कारण भारत से मिली प्राचीनतम सांस्कृतिक धरोहरों में गिने जाते हैं। भगवान बुद्ध के अस्थि कलशों में रखे होने के कारण उनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व उहें अनमोल बनाता है। बुद्ध, रामायण और गांधी भारत के सबसे बड़े वैचारिक और सांस्कृतिक निर्यात हैं। इनके विश्वव्यापी प्रभाव के सामने तूतनखामून के स्मारक से मिले पुरावशेष, ऐंथ्रेस के मंदिर से मिली संगमरमर की शिल्पकृतियाँ और नाइजीरिया के बेनिन शहर से मिली कांस्य प्रतिमाएं कहीं नहीं ठहरती जिनके प्रत्यर्पण को लेकर दशकों से विवाद चल रहा है। सोटीबोज़ को उम्मीद है कि बुद्ध के श्रद्धार्थों की बोली 100 करोड़ रुपये तक जा सकती है। लेकिन भगवान बुद्ध जैसे महापुरुष की अस्थियों से जुड़े रत्नों की नीलामी होना ही नैतिक आद्यार पर सही नहीं प्रतीत होता। क्या आप इतालीवी शहर ट्यूरिन के गिरजे में रखे इसा के कफ़न की नीलामी की कल्पना कर सकते हैं? इसा और उनके परिवार से सीधे जुड़े अवशेषों की नीलामी नहीं की जा सकती। इसी तरह अच्छा होता कि यूनेस्को पिपरहवा के स्तूप और उसकी खुदाई से मिली पुरातात्त्विक सामग्री को विश्व धरोहर घोषित कर देता और इस नीलामी पर रोक लग जाती। या फिर दलाई लामा ही इसे रुकवाने और रत्नों को लौटाकर पिपरहवा में लोगों के दर्शन और पूजन के लिए रखवाने का प्रबंध करते। भारत सरकार ने 2009 में महात्मा गांधी के चश्मे, घड़ी और चप्पलों की नीलामी को स्वकावने की कोशिश की थी। अंत में विजय माल्या ने बोली लगाकर उन्हें भारत लौटाने में मदद की थी। सुना है अब भारत सरकार भगवान बुद्ध की इस अनमोल धरोहर के प्रत्यर्पण का प्रयास कर रही है जो सराहनीय कदम है।

(लेखक लंदन में पत्रकारिता संस्कृतिकर्म व अध्यापन में सक्रिय है।)

ऑपरेशन सिंदूर : एक पूर्व-सुनिश्चित नाकामी का योजनाभव्य

महिलाओं की उपरिथित उत्साहवर्धक नहीं है

सना मेरा-पुरुष समानता सुनाश्यत करने मेरात का प्रगत धीमी रही है। बावजूद इसके, महिलाएं तमाम चुनौतियों को पार करते हुए सेना के तीनों अंगों मेरे अपनी जगह बना रही हैं और धीरे-धीरे अग्रणी भूमिका मेरी दिखने लगी हैं। मगर यह संख्या अब भी संतोषजनक नहीं है। पुरुषों के मुकाबले जिस अनुपात मेरी महिलाओं को सेना मेरे अवसर मिलना चाहिए, उस पर प्रायः सवाल उठते रहे हैं। कोई दोशिय नहीं कि जब जीवन के हर क्षेत्र मेरी महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिला कर घल रही हैं, तो सैन्य बलों मेरे उनकी प्रतिभागिता पर्याप्त स्पष्ट से क्यों नहीं बढ़ाई जानी चाहिए? अभी सेना मेरी महिलाओं की उपस्थिति कोई बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने उचित ही सवाल किया है कि जब महिलाएं रफाल उड़ा सकती हैं, तो सेना की कानूनी शाखा मेरे उनकी संख्या सीमित क्यों है। वे शीर्ष पदों पर क्यों नहीं नियुक्त हो सकतीं। स्थायी कमीशन के लिए भी सेना मेरे कार्यरत महिलाओं को लंबा संघर्ष करना पड़ा था। अपने अधिकारों के लिए उन्हें कानूनी लड़ाई लड़ी थी। तब शीर्ष न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद सेना मेरे उच्च पद पर उनके पहुंचने का सास्ता खुला था। ऋषि-पुरुष समानता के सवाल पर अदालते सरकार को अपनी मानसिकता बदलने की नसीहत देती रही है। महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का फैसला सुनाते समय भी जब अदालत ने सरकार को टोका था, तो उसका कहना था कि दस्ता बलों मेरे पुरुष अभी महिला अधिकारियों की कमान स्वीकार करने के लिए मानसिक स्पष्ट से प्रशिक्षित नहीं हो पाए हैं। मगर अब तो अग्रिम मार्गे मेरी महिलाएं कई अहम भूमिकाएं निभाने लगी हैं। सीमित संख्या मेरी ही सही, अगर महिलाएं युद्धक विमान उड़ाने के काबिल हो गई हैं, तो क्या पुरुष वर्द्धक की मानसिकता नहीं बदलनी चाहिए। सेना की विभिन्न शाखाओं मेरी महिलाओं की संख्या बढ़ाने के साथ उन्हें युद्ध क्षेत्र मेरे क्यों नहीं तैनात किया जाना चाहिए। आज सेना की सभी चिकित्सा सेवाओं का नेतृत्व महिलाएं ही कर रही हैं। इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए कि बाकी सेवाओं मेरी अग्रणी भूमिका से उन्हें क्यों वंचित रखा जाए।

जैसा कि आसानी से अनुमान लगाया जा सकता था, ऑपरेशन सिंट्रॉ के अचानक पटक्षेप के बाद, उसे 'कामयाब' साबित करने की विभिन्न स्तरों पर कोशिशें शुरू हो गयी हैं। बेशक, खुद प्रधानमंत्री ही नहीं, उनके बाद दूसरे-तीसरे नंबर के दावेदार राजनीतिक नेताओं ने भी, पहले चरण में चुप रह कर, इसके जबर्दस्त प्रयास में सेन्य प्रतिष्ठान को ही सबसे आगे धकेला है। डीजीएमओ और तीनों सेनाओं के शीर्ष प्रतिनिधियों की एक साझा पत्रकार वार्ता में जहां एक ओर, यह स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी कि 10 तारीख की शाम से हुई जगबंदी, पाकिस्तानी डीजीएमओ की फोन करने की पहल के बाद, दोनों पक्षों में बनी सहमति से हुई थी, न कि अमेरिका की मध्यस्थता से हुई थी। वहाँ दूसरी ओर यह दिखाने की भी कोशिश की जा रही थी कि इस तीन दिन की लड़ाई में, पाकिस्तानी आतंकवादी टिकानों को ही नहीं, पाक सेना को भी बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि भारत को उसकी तुलना में बहुत ही कम नुकसान उठाना पड़ा है। यानी 7 से 10 मई तक का यह ऑपरेशन, भारत की नजर से कामयाब रहा है। इसी के समानांतर, सत्ताधारी संघ-भाजपा के आईटी सेल और उससे निर्देशित ट्रोल सेना ने कम से कम तीन धारणाएं बनाने के लिए अपनी ताकत ऊँक दी है। पहली यह कि जो जंगबंदी हुई है, वह वास्तव में जंगबंदी से कमतर कोई चीज है। ऑपरेशन सिंट्रॉ भी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वह तो बराबर जारी है। दूसरे, इस संक्षिप्त कार्रवाई में मोदी सरकार ने बता दिया है कि अब हरेक आतंकवादी कार्रवाई का जबाब इसी तरह पाकिस्तान के अंदर प्रहार से दिया जाएगा। तीसरे, पाकिस्तान को भारत की प्रहार शक्ति का अंदाजा हो गया है और अब वह भारत के खिलाफ कोई शरारत करने से पहले दस बार सोचेगा। आगे वाले दिनों में बार-बार दोहराने के जरिए, 'जीत' के इन दावों को और कई गुना फुलाने की ही कोशिश नहीं की जा रही हो, तो ही हैरानी की बात होगी। विंडंबानापूर्ण तरीके से यहाँ उनके लिए गोदी मीडिया का वह कुख्यात रूप से अतिरिक्त प्रचार भी, किसी न किसी तरह से प्रयोग में आ रहा हो सकता है, जिसकी इस तरह प्रचार उपयोगिता को ही पहचान कर, सत्ताधारी ताकतों ने आधिकारिक स्तर पर उनके ऊँजुलूल दावों से दूरी बनाने के बाबजूद, उन्हें रोकना तो दूर, टोकने तक की कोई जरूरत नहीं समझी थी। दूसरी ओर, लड़ाई के संदर्भ में फेक न्यूज और भारत-विरोधी खबरों पर अंकुश लानाने के नाम पर, मोदी सरकार के प्रति आलोचात्मक रुख रखने वाले कई यूट्यूब चैनलों सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक्स पर एक साथ पूरे आठ हजार खातों को रोकने के लिए, जबर्दस्त सरकारी प्रहार किया गया था। इसी सिलसिले में लोकप्रिय डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म, द वायर तक पर सरकार की गाज गिरी थी। ऐसी ही गाज़ चर्चित पत्रकार, पुण्यप्रसून वाजपेयी के यूट्यूब चैनल पर भी गिरी थी। बहरहाल, ये सारी प्रचार कोशिशें अपनी जगह, सत्ताधारियों के लिए अपनी समर्थक कतारों से भी इस अचानक खत्म हुई लड़ाई को अपनी और सबसे बढ़कर नरेंद्र मोदी की जीत मनवाना, आसान नहीं हो गहा है। इसके सबूत के तौर पर हम, 10 तारीख की शाम संवाददाता सम्मेलन में युद्ध विशम की घोषणा करने मात्र के लिए, विदेश सचिव मिस्त्री को ही नहीं, उनके पूरे परिवार को ही, जिस तरह की भीषण ट्रोलिंग का समाना करना पड़ रहा है, उसे रखना चाहते हैं। कहने की जरूरत जरूरत नहीं है कि इस संक्षिप्त लड़ाई के दौरान खासतौर पर देश का चेहरा बने रहे विदेश सचिव के परिवार की इस तरह की भीषण ट्रोलिंग शर्मनाक है। लेकिन, सिर्फ उक्त निर्णय की घोषणा करने के लिए मिस्त्री की इस तरह की ट्रोलिंग से साफ हो जाता है कि 'जीत' का नैरेटिव, खुद सत्ताधारी संघ-भाजपा की कतारों के गले से नीचे नहीं उत्तर रहा है और वे अपना फ़स्टेन निकालने के लिए किसी अपेक्षाकृत कमज़ोर शिकार की तलाश में हैं। कमज़ोर

शिकार की तलाश में इसलिए कि वास्तव में जंगबंदी का फैसला लेने वालों, नंबर बन, नंबर टू आदि के निर्णय पर सीधे सवाल उठाने की, उनमें हिम्पट नहीं है। इस संघी ट्रोल सेना के मिस्त्री पर इस तरह झापट पड़ने के खिलाफ सत्तापक्ष से इन पंक्तियों के लिखे जाने तक किसी ने चूं तक नहीं की थी। इसकी वजह समझना मुश्किल भी नहीं है। इस तरह की सेना को, शिकारी कुत्तों की तरह लहकाया तो जा सकता है, लेकिन अंकुश में नहीं रखा जा सकता। यहीं इस परिघटना का चारित्र है। इस सिलसिले में आईएएस एसोसिएशन के अलावा शासन की ओर से किसी के हस्तक्षेप न करने से बरबस, कई साल पहले की घटना याद आ जाती है। तब नंदें द्रोल सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान, तब तक भाजपा के शीर्ष नेताओं में मानी जाने वाली, तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को, उनके मंत्रालय से जुड़े किसी छोटे से काम के लिए, जो इस ट्रोल पलटन को नागवार गुजरा था, भीषण तरीके से ट्रोल किया गया था। बुजुर्ग नेता के पति तक को इसमें नहीं बकशा गया था। इसके बावजूद, उस समय भी संघ-भाजपा का कोई नेता, सुषमा स्वराज की हिमायत में सामने नहीं आया था। बहरहाल, इतने पीछे क्यों जाएं। मिस्त्री से चंद रोज पहले ही, पहलगाम में ही आतंकवादियों के हाथों मारे गए नौसेना अधिकारी की विधवा, हिमांशी नरवाल को इसी संघी ट्रोल सेना ने सिर्फ इतना कहने के लिए बुरी तरह से ट्रोल किया था कि हमें न्याय चाहिए, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि कश्मीरियों के, मुसलमानों के पीछे पड़ जाया जाए। और यह भी संयोग ही नहीं है कि हिमांशी नरवाल और मिस्त्री की पुत्री, दोनों को ही उनके जेन्नयू कनेक्शन के हवाले से इस ट्रोलिंग का निशाना बनाया गया है। बेशक, जिस तरह से यह युद्धविराम हुआ है, इस संघी ट्रोल सेना में ही नहीं, आम लोगों में भी उस पर काफी असंतोष है। इस असंतोष की एक वजह तो यह युद्ध विराम, अमेरिका के हस्तक्षेप से होना ही है। सभी जानते हैं कि शिमला



वमन इंपावरमेट : जिम्मेदारियों का बोझ

विजय गर्ड
औरतों के रोजमरा के जीवन पर आधारित फ़िल्म 'पिसेज' इन दिनों काफी चर्चा में है। इस फ़िल्म एक ऐसी महिला की कहानी को दिखाया गया जिस की चाहत और सपने सिलबड़े पर चटनी की तरह पिस कर रह गए। इस फ़िल्म में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे शादी के बाद एक महिला का जीवन घर की चारदीवारी में घुट कर रह जाता है। कैसे एक महिला का सारा जीवन घरपरिवार की देखभाल और किचन में ही बीत जाता है। घरेलू कामों का नाता लड़कियों के जीवन से जुड़ा हुआ है। भले ही कोई लड़की किसी समाज, परिवार में पैदा हुई हो, उसे बचपन से ही घर के कामों की शिक्षा दी जाती है यह कह कर कि उसे दूसरे घर जाना है। बुजुर्गों का कहना है कि चाहे लड़कियां कितनी ही पढ़ लिख जाएं पर अपनी समुराल जा कर उठें बनानी तो रोटियां ही हैं। सदियों से एक प्रथा चली आ रही है कि चाहे जो भी हो, घर के कामों की

जिम्मेदारी तो महिलाओं की ही बनती है। उन्हें यह एहसास दिलाया जाता है कि खाना पकाना, कपड़े धोना, बरतन मांजना और घर के सभी सदस्यों का खायाल रखना महिला की ही जिम्मेदारी है। एक ही परिवार में लड़कों को पूरी आजादी दे दी जाती है और लड़कियों को रीतिरिवाजों और संस्कारों की बेड़ियों में बांध दिया जाता है। घर की जिम्मेदारियों के साथ उन्हें धार्मिक कर्मकांडों का भी हिस्सा बनना पड़ता है। आए दिन ब्रतउपवास भी करने पड़ते हैं, चाहे उन की मरजी हो या न हो या चाहे वे शारीरिक रूप से कमज़ोर ही क्यों न हों, उन्हें अपने बेटे, पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह सब करना ही पड़ता है। लेकिन समाज ने पुरुषों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है। कोई क्यों नहीं समझता शालिनी वकिंग वूमन है। रोज सुबह 4 बजे उठ जाती है। घर का सारा काम करती है, नाश्ता बना कर, बच्चों को उठा कर उन्हें तैयार कर स्कूल भेजती है। फिर

साथ ऐसा नहीं है, उसे तो रोज टाइम से औफिस जाना होता है। वह कहती है कि मन करता है नौकरी छोड़ दूँ। लेकिन बढ़ती महंगी और फिर बच्चों की महंगी शिक्षा को देखते हुए नौकरी भी नहीं छोड़ सकती है। यह कहानी केवल शालिनी की नहीं है बल्कि दुनिया की लगभग सभी औरतों की है। खुद के लिए समय नहीं माधुरी टीचर है और पति, आलोक भी इसी फील्ड में हैं। दोनों एक ही समय स्कूल के लिए निकलते हैं और घर भी सेम टाइम पहुंचते हैं। लेकिन घर आ कर जहां आलोक टीवी खोल कर बैठ जाते हैं, फोन पर दोस्तों से हाहा, हीही करते हैं, रिल्स देखते हैं, वही माधुरी किचन में खाना पकाने घुस जाती है, बच्चों का होमवर्क करती है और फिर बिखरे हुए घर को व्यवस्थित करती है क्योंकि सुबह उस के पास इतना टाइम नहीं होता कि यह सब कर सके।

